



भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में
बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री राम नाथ कोविन्द

का

अभिभाषण

25 फरवरी, 2016

बिहार विधान मण्डल के माननीय सदस्यगण :

राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की आकांक्षा के साथ नये वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सब को शुभकामना देता हूँ। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कार्य सम्पन्न होने हैं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति का मार्ग और प्रशस्त होगा। आपसे अपील है कि सत्रावधि में अपने रचनात्मक विचारों से सरकार का मार्गदर्शन करेंगे।

2. बिहार की जनता द्वारा विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए अपार बहुमत से शासन का दायित्व दिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार ने समाज के कमजोर, साधनहीन एवं विकास से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देते हुए बिहार के बहुमुखी विकास के लिए ठोस कदम बढ़ाये हैं। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास को और गति देने की प्रतिबद्धता के साथ नये संकल्प लेने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से सरकार के गठन के पश्चात् "न्याय के साथ विकास" के संकल्प को दोहराते हुए आगामी पाँच वर्षों में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 तैयार कर इसे संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। आशा है, समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए ये ठोस कार्यक्रम सिद्ध होंगे।

3. राज्य सरकार के कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश की जो नीतियाँ एवं कार्यक्रम हैं वे मजबूती के साथ आगे भी जारी रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और महादलित, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के विकास एवं कल्याण की अनेक योजनाएँ जो सफलतापूर्वक चल रही हैं, इन सभी को और सुदृढ़ करते हुये क्रियान्वित करते रहेंगे। अब सरकार द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" को सुशासन का लक्ष्य पाने के लिए स्वीकार किया गया है जिसे मिशन मोड में क्रियान्वित किया जायेगा। ये सात निश्चय हैं—आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, हर घर बिजली लगातार, घर तक पक्की गली नालियों एवं अवसर बढ़ें आगे पढ़ें।

4. राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विधि-व्यवस्था संधारित कर कानून का राज स्थापित करने की रही है। राज्य में अपराधों पर निरन्तर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। अपराध के प्रमुख शीर्षों में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा वर्ष 2014 के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कुल संज्ञेय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर प्रति लाख जनसंख्या 229.2 है। देश में बिहार 174.2 के दर के साथ 22वें स्थान पर है। लोग भयमुक्त वातावरण में जीवन-यापन कर रहे हैं। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाये रखने के लिए कोई समझौता नहीं किया जायेगा। आज राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का वातावरण है। सभी वर्गों एवं सम्प्रदायों के बीच आज स्नेह, विश्वास एवं सामंजस्य है।

5. अनुसंधान एवं विधि-व्यवस्था की जिम्मेवारी का पृथक्कीकरण निर्धारित समय सीमा में करने के लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय में हेल्प लाइन के साथ 24x7 आधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि

राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आपराधिक अथवा विधि-व्यवस्था से संबंधित सूचना का त्वरित संप्रेषण कर सके और संबंधित मामले में क्षेत्रीय स्तर से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। जिलावार-थानावार आपराधिक घटनाओं का वर्गीकरण एवं मानचित्रण करके समीक्षा की जा रही है। महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के विरुद्ध घटित घटनाओं को पूरी गंभीरता से लेते हुए ऐसे अपराधों के विरुद्ध प्रभावकारी रणनीति बनाकर कार्रवाई की जा रही है। एसिड से होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एसिड बिक्री को नियंत्रित करने तथा पीड़ितों को उचित ईलाज एवं मुआवजा देने की कार्रवाई की गयी है। साथ-साथ नौकरी में आरक्षण की सुविधा भी देने का निर्णय लिया गया है।

6. राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुँचाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक से सिपाही तक के संवर्गों में कुल 43 हजार 761 पदों का सृजन किया गया है, जिसकी भर्ती पाँच चरणों में प्रस्तावित है। सिपाही के पद पर वर्ष 2006 से अब तक कुल 22 हजार 813 नियुक्तियाँ की गयी हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 11 हजार 464 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अबतक 2 हजार 152 नियुक्तियाँ की गयी हैं तथा कुल 1 हजार 140 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

7. वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, पटना के अतिरिक्त दो क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर की स्थापना की जा रही है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पुलिस अकादमी, विभिन्न थाना भवनों, आवासीय भवनों, पुलिस लाइन, कारा भवन, पुलिस बैरक, शौचालय आदि सहित कुल 483 भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है और 386 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है।

8. राज्य की काराओं में मुलाकाती परिसर एवं मुलाकाती प्रबंधन व्यवस्था की योजना के अन्तर्गत आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर सहित अन्य 21 काराओं में निर्माण कार्य चल रहा है जो पूर्ण होने की स्थिति में है। राज्य की 58 काराओं में नये सिरों से सुरक्षात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का अधिष्ठापन तथा काराओं एवं न्यायालयों के बीच बंदियों के उपस्थापन हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का अधिष्ठापन किया जा रहा है। अधिष्ठापन कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जायेगा।

9. राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति का अनुसरण करते हुए राज्य प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु कृत संकल्पित है। लोक सेवकों द्वारा अर्जित अवैध सम्पत्ति के अधिहरण हेतु बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत राज्य के विशेष न्यायालयों में 57 वाद दायर किये गये हैं, जिनमें 53 करोड़ 14 लाख रुपये निहित हैं। अब तक कुल 6 मामले में सम्पत्ति अधिहृत की गयी है। अब तक कुल 734 ट्रेप के मामलों में 797 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें वर्ष 2015 में कुल 53 ट्रेप के मामले दर्ज किये गये हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष निगरानी इकाई द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में अब तक कुल 119 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2015 में 17 मामले दर्ज किये गये हैं। भ्रष्टाचार के लिए पदों के दुरुपयोग से संबंधित अब तक कुल 344 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें वर्ष 2015 में 40 मामले दर्ज किये गये हैं। प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्ट के अन्तर्गत

9 अभियुक्तों की परिसम्पत्तियों अंतिम रूप से जब्त की जा चुकी हैं, जिनका मूल्य करीब 15 करोड़ 10 लाख रुपये हैं।

10. निगरानी मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये तथा प्रत्यानुपातिक धनोपार्जन एवं पद के दुरुपयोग संबंधी अनियमितताओं के 1 हजार 109 मामलों में विभागीय कार्रवाई संचालित कर 530 कर्मियों को सेवा से बर्खास्तगी या पेंशन जर्बती का दंड दिया गया है एवं 134 कर्मियों को अन्य दण्ड दिया गया है।

11. राज्य का योजना उद्व्यय वर्ष 2015-16 में बढ़कर 51 हजार 128 करोड़ रुपये हो गया है। राज्य का अपना कर-राजस्व वर्ष 2014-15 में बढ़कर 20 हजार 750 करोड़ रुपये हो गया है तथा वर्ष 2015-16 में 30 हजार 875 करोड़ रुपये के कर राजस्व का अनुमान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व बचत 11 हजार 981 करोड़ रुपये तथा राजकोषीय घाटा 13 हजार 584 करोड़ रुपये अनुमानित है। यह राजकोषीय घाटा विगत वर्षों की भांति बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अनुसार निर्धारित अधिसीमा 3 प्रतिशत के अधीन है, जो कुशल वित्तीय प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। पिछले पंचवर्षीय योजना काल में सरकार ने अपने योजना एवं गैर-योजना व्यय में काफी वृद्धि की है परन्तु ऋण को धारणीय सीमा में रखा गया है। वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2014-15 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4 लाख 2 हजार 283 करोड़ रुपये एवं वार्षिक वृद्धि दर 17.06 प्रतिशत था जो देश के औसत वृद्धि दर से अधिक है।

12. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित 51 सेवाओं में 11 फरवरी, 2016 तक प्राप्त कुल 12 करोड़ 57 लाख आवेदनों में से 12 करोड़ 48 लाख आवेदन निष्पादित किये गये हैं। राज्य की जनता द्वारा समर्पित किये जानेवाले शिकायतों का विनिर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण कराये जाने के उद्देश्य से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। अब नागरिकों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई एवं निवारण का अवसर एक नियत समय-सीमा के अंदर मिल सकेगा। शीघ्र ही सभी तैयारी पूर्ण कर इसे मई, 2016 से लागू किया जायेगा।

13. राज्य के समग्र विकास में मानव विकास की विशिष्ट भूमिका है और मानव संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए प्रारंभ से ही सरकार ने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही बहुआयामी रणनीति अपनाते हुए सभी वंचित वर्गों को स्कूल पहुँचाने, नामांकन में वृद्धि लाने, नये प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने, शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने एवं लड़के-लड़कियों के बीच शिक्षा की खाई को पाटने के लिए अनेक नवाचारी कदम उठाये गये हैं। इन सभी प्रयासों का समेकित परिणाम है कि स्कूलों से वंचित बच्चों की संख्या में निरंतर कमी आयी है और स्कूलों में विशेषकर लड़कियों की उपस्थिति बढ़ी है। वर्ष 2005 में 06-14 आयु वर्ग के लगभग 12 प्रतिशत बच्चे विद्यालय से बाहर थे जो अब घटकर मात्र 0.86 प्रतिशत ही रह गया है।

14. सर्व शिक्षा अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के आलोक में अब तक 21 हजार 100 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं, 19 हजार 581 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है, 11 हजार 416 नये प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य

पूर्ण किया गया है तथा 2 लाख 44 हजार 80 नये वर्गकक्षों का निर्माण पूर्ण हो गया है एवं शेष कार्य वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जायेगा। मुख्यमंत्री बालक-बालिका पोशाक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में कुल 1 करोड़ 52 लाख 81 हजार 137 बालक-बालिकाओं को पोशाक की राशि उपलब्ध करायी गयी है। मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में 9वीं कक्षा में नामांकित 17 लाख 35 हजार 960 छात्र-छात्राओं को साईकिल के लिए निधि उपलब्ध करायी गयी है। राज्य में इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत 2 करोड़ 3 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

15. वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 78 हजार 948 छात्राओं एवं उच्च जाति के 30 हजार छात्रों को राशि उपलब्ध करायी गयी है। सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का नगदी हस्तांतरण के लिए बच्चों के माता-पिता-अभिभावक के खाता का संधारण किया जा रहा है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि सीधे खाते में हस्तांतरण करने की योजना है।

16. राज्य सरकार द्वारा राज्य के 4 हजार 500 माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत इस वर्ष 1 हजार 160 नये विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है। अब तक 2 हजार 157 मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना के तहत 832 विद्यालयों में कम्प्यूटर अधिष्ठापित हो चुके हैं एवं कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के लिए "मिशन गुणवत्ता" नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जो राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को सुनिश्चित कराने में कारगर साबित हो रहा है। राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढीकरण एवं प्रशिक्षण में गुणवत्ता के विकास हेतु विश्व बैंक के साथ राज्य सरकार ने एकशरनामा किया है। परियोजना की अवधि वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 है।

17. राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कुल 11 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुल 5 प्रस्तावों को समीक्षोपरांत निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापना हेतु एल.ओ.आई. निर्गत हो चुका है। राज्य में आई आई. एम. की स्थापना हेतु मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के परिसर में लगभग 119 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है। इस संस्थान में सत्र 2015-16 से पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है।

18. बिहार देश के सबसे युवा-बहुल राज्यों में से एक है। बिहार की नयी पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए सक्षम बनाना राज्य के 'न्याय के साथ विकास' की नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सरकार का निश्चय है - "आर्थिक हल, युवाओं को बल"। अतः निश्चय के अनुरूप युवाओं के लिये विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु जिला मुख्यालय में युवाओं के लिए पंजीकरण एवं रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापित करने की योजना है, लगभग 4 करोड़ की लागत के इस केन्द्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं का पंजीकरण होगा। पंजीकरण के उपरान्त उन्हें तीन विकल्पों यथा- स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, भापा-संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर-ज्ञान कौशल और स्वयं सहायता भत्ता में से पात्रता के अनुसार कोई

एक विकल्प से लाभान्वित किया जा सकेगा। सभी जिलों में एक या एक से अधिक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के भवन निर्माण के लिए 155 करोड़ रुपये के संभावित व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

19. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कोई भी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा हेतु ऋण लेने के लिए इच्छुक हों, को बैंक के माध्यम से शिक्षा ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के तहत अधिकतम 4 लाख रुपये तक ऋण मुहैया कराया जा सकेगा जिसके लिए बैंकों को गारंटी एवं वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जायेगी। योजना की पात्रता रखने वाले सभी विद्यार्थियों को अपना पंजीकरण, जिला पंजीकरण एवं परामर्श केन्द्र में करवाना होगा जहाँ से उसके आवेदन को संबंधित बैंक में भेजा जायेगा और विद्यार्थी को स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में कम से कम 5 लाख विद्यार्थियों के आच्छादन का लक्ष्य है।

20. "स्वयं सहायता भत्ता" योजना के तहत 12वीं कक्षा पास 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे युवक/युवतियों जो अध्ययनरत नहीं हों तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों, को अधिकतम दो वर्षों के लिए प्रति माह एक हजार रुपये की दर से स्वयं सहायता भत्ता उपलब्ध कराया जायेगा। यह भत्ता युवा वर्ग को रोजगार तलाशने में सहायक होगा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजना को लागू करने के लिए 1 हजार 216 करोड़ रुपये के संभावित व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

21. जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में निबंधित 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी अगर भाषा-संवाद एवं बुनियादी कंप्यूटर-ज्ञान कौशल प्राप्त करने के लिए इच्छुक है तो उन्हें प्रखंड स्तर पर स्थापित कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान के साथ-साथ अन्य कौशल प्राप्त करने के लिए संबद्ध किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वैसे छात्र/छात्राएँ जो 10वीं उत्तीर्ण हैं तथा आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं एवं 15-20 वर्ष आयु वर्ग के हैं और कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके आवेदन भी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में प्राप्त किये जायेंगे और उन्हें रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

22. राज्य के 14 विश्वविद्यालय परिसर एवं 262 संबद्ध महाविद्यालयों में निःशुल्क वाई-फाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 185 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना का क्रियान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से कराया जायेगा।

23. सरकार का एक निश्चय "अवसर बढ़ें, आगे बढ़ें" के तहत राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला एवं अनुमण्डल में उच्च, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. स्कूल एवं प्रत्येक अनुमंडल में ए.एन.एम. स्कूल के संकल्प के अन्तर्गत 20 नये जी.एन.एम. स्कूल एवं 63 नये ए.एन.एम. स्कूल खोले जाने हेतु कुल अनुमानित 638 करोड़ रुपये की निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है। 5 नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला स्तर पर 24 पैरा-मेडिकल संस्थान खोले जाने हेतु कुल अनुमानित 2 हजार 120 करोड़ रुपये की

निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है। चिकित्सा महाविद्यालयों में 16 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु कुल अनुमानित 528 करोड़ रुपये की निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है।

24. प्रत्येक जिला में पॉलिटैकनिक एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के संकल्प के आलोक में 11 जिलों में पॉलिटैकनिक की स्थापना एवं 26 जिलों में नये अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 841 करोड़ रुपये एवं 3 हजार 15 करोड़ रुपये की निश्चय योजना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए दी गयी है। सभी जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संकल्प के आलोक में 22 जिलों में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 54 अनुमंडलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2016-17 से करने हेतु क्रमशः 399 करोड़ एवं 1 हजार 507 करोड़ रुपये की निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है।

25. स्वास्थ्य सेवाओं के विकास की दिशा में सरकार ने काफी प्रगति की है। मातृ-स्वास्थ्य के लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि में प्रसव के साथ अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। नवजात शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु-दर में कमी लाने के लिए नवजात शिशु देखभाल हेतु 510 केन्द्र, नवजात शिशु स्थिरीकरण हेतु 35 इकाई, विशेष नवजात देखभाल हेतु 22 इकाई संस्थापित हैं तथा नवजात शिशुओं की घर पर आशा कार्यकर्ताओं द्वारा नियमित भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए 36 पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गयी है। राज्य में प्रतिरक्षण संबंधी उत्तरोत्तर आच्छादन हेतु 14 जिलों में मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम एवं 24 जिलों में मुख्यमंत्री सघन टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है। फलस्वरूप राज्य में पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन डब्ल्यू.एच.ओ. के विश्लेषण के अनुसार 82 प्रतिशत पहुँच गया है। राज्य के 0-18 वर्ष के बच्चों में सम्यक वृद्धि एवं विकास हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जुलाई, 2015 से शुरू किया गया है एवं स्वास्थ्य जॉचोपरान्त अद्यतन 68 लाख 51 हजार 904 बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया है।

26. नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार करने हेतु राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक के वाह्य कक्ष में मरीजों का निबंधन, दवा वितरण, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी जाँच की सुविधा हेतु कम्प्यूटरीकृत प्रणाली "संजीवनी" के तहत 5 करोड़ 30 लाख से अधिक मरीजों की सूचना दर्ज की गयी है।

27. स्वास्थ्य क्षेत्र में द्वितीय चरण के सुधार कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। राज्य के 534 प्रखण्डों में न्यूनतम एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 24x7 संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक जिले के दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी की सेवा आरम्भ की जा रही है। सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में एवं 36 जिला अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन मशीन एवं डायलिसिस की सुविधा आरम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी जिला अस्पतालों में नेत्र एवं चर्म रोग के ओ0पी0डी0 तथा गहन चिकित्सा कक्ष की स्थापना, फिजियोथेरेपिस्ट एवं ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट की नियुक्ति तथा फिजियोथेरेपी यूनिट की स्थापना, डायलिसिस, एम0आर0आई0 एवं सी0टी0 स्कैन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

28. इसके अतिरिक्त सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर में अस्थि रोग, राजेन्द्र नगर अस्पताल में चक्षु रोग तथा गार्डिनर रोड अस्पताल में ग्रन्थि रोग हेतु विशिष्ट इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट अस्पतालों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

29. बिहार में सड़कों तथा पुल-पुलियों का जाल बिछाकर सुदूर क्षेत्रों एवं लोगों को इससे जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है। हमने राज्य के हर सुदूर क्षेत्र से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अब इस लक्ष्य को घटाकर 5 घंटे कर दिया गया है और इसके लिए योजनाबद्ध कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। आधारभूत संरचना के निर्माण से हमने न केवल सुदूर क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान की बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों को भी जोड़ने का काम किया है। पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग दोनों ने मिलकर अब तक 74 हजार किलोमीटर से अधिक वृहद् और ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा उन्नयन किया है। अभिगम्यता बढ़ाने हेतु 6 हजार 282 वृहद्-लघु पुलों का भी निर्माण कराया है। नई आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ-साथ उसके रख-रखाव के लिए भी नीति बनाई गयी है। सरकार राज्य उच्च पथों, वृहद् जिला पथों के साथ-साथ ग्रामीण पथों के अनुरक्षण पर भी काम कर रही है।

30. पटना स्थित जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड) पर जगदेव पथ से शेखपुरा मोड़ तक ऊपरी राजमार्ग एवं धिरैयाटांड ऊपरी पुल का गांधी मैदान तक विस्तारीकरण योजना का लोकार्पण किया गया है। पटना शहर स्थित मीठापुर आर0ओ0बी0 से स्टेशन होते हुए धिरैयाटांड ऊपरी पुल तक विस्तारीकरण, लोक नायक गंगा पथ (दीघा से दीदारगंज) एवं पटना स्थित एम्स से दीघा तक एलिवेटेड कोरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति में है। पटना शहर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड) पर ललित भवन से विद्युत भवन के बीच लोहिया पथ चक्र तथा मीठापुर ऊपरी पुल से भिखारी ठाकुर (यारपुर) ऊपरी पुल (भाया आर. ब्लॉक जंक्शन) के बीच फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

31. राज्य के 250 या उससे अधिक आबादी वाले सभी बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नये पथों के निर्माण के साथ-साथ पूर्व निर्मित ग्रामीण पथों के सुदृढीकरण एवं अनुरक्षण कार्य हेतु राज्य सरकार कृत-संकल्प है। आधारभूत संरचना सृजन के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार का निश्चय है "घर तक, पक्की गली-नालियाँ"। इसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त, शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा तथा सभी गाँव एवं शहरों में गली-नाली का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना को स्वीकृति दे दी गयी है एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

32. औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र के विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्पादन, वितरण एवं संचरण के प्रक्षेत्र में परियोजनाओं को तीव्र गति से कार्यान्वित किया जा रहा है। उत्पादन प्रक्षेत्र में मुजफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठान की 110 मेगावाट की दोनों इकाइयों का आधुनिकीकरण कर उत्पादन शुरू हो चुका है। साथ ही निर्माणाधीन 195 मेगावाट की दो नई इकाइयों के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का लक्ष्य है। बरौनी ताप

विद्युत प्रतिष्ठान की 110 मेगावाट की दोनों इकाइयों का आधुनिकीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा। साथ ही 250 मेगावाट की दो नयी इकाइयों का कार्य निर्माणाधीन है जिसे 2016-17 तक पूरा करने का लक्ष्य है। नवीनगर में स्टेज-1 एवं स्टेज-11 के तहत 660 मेगावाट की तीन-तीन इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

33. राज्य में संचरण के क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। वर्तमान में 3 हजार 459 मेगावाट ईवैक्यूएशन की क्षमता हासिल की जा चुकी है और इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक इसे 5 हजार मेगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है। स्पेशल प्लान के अन्तर्गत 7 ग्रिड उपकेन्द्रों का निर्माण, 47 ग्रिड उपकेन्द्रों में संचरण क्षमता वृद्धि, 4 हजार 480 सर्किट किलोमीटर नये संचरण लाईनों का सुदृढीकरण, 13 पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों का जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण एवं पटना में संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है।

34. राज्य में वितरण के प्रक्षेत्र में परियोजनाओं को तीव्र गति से कार्यान्वित कराया जा रहा है। स्पेशल प्लान के अन्तर्गत फेज-1 के तहत स्वीकृत योजनाएँ मुख्यतः वितरण कम्पनियों के विद्युत संरचना की सुदृढीकरण से संबंधित हैं तथा फेज-2 के तहत स्वीकृत योजना का उद्देश्य 2016-17 के पीक लोड के मांग को पूरा करने हेतु वितरण संरचनाओं के नव निर्माण से संबंधित है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 2 हजार 944 अदद अविद्युतीकृत गाँवों में से 1 हजार 864 अदद गाँवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, शेष 1 हजार 80 गाँवों को अभियान चलाकर शीघ्र विद्युतीकृत कर दिया जायेगा।

35. सरकार के निश्चय - "हर घर बिजली लगातार" के तहत राज्य के बचे हुए सभी गाँव और बसावटों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया जाएगा तथा सरकार अपने संसाधनों से सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करायेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना की स्वीकृति दी गयी है जिसके तहत हर घर को विद्युत संबंध देने हेतु कुल 1 हजार 897 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गयी है।

36. राज्य में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप को लागू किया जा रहा है। कृषि रोड मैप के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज, नये-नये कृषि यंत्र, वर्गी कम्पोस्ट तथा फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि के उन्नतशील तौर-तरीकों से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इस दिशा में मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं बीज ग्राम योजना कार्यक्रम काफी सफल रहे हैं। धान, गेहूँ, दलहन एवं मक्का की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए वैज्ञानिक विधियों से खेती के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्षण का आयोजन किया गया। कृषि विकास के लिए राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों के कारण आज राज्य में गेहूँ, चावल एवं मक्का की उत्पादकता, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके अतिरिक्त दलहन, तेलहन एवं कुल खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादकता में भी वृद्धि दर्ज की गयी है।

37. राज्य के सभी किसानों को 3 वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके तहत अब तक 7 लाख 21 हजार 330 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं। अब तक 285 प्रखंडों में ई-किसान भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। राज्य में बागवानी के विकास के लिए वर्ष 2015-16 में अबतक 17 लाख पौधों का वितरण किसानों के बीच किया गया है। चण्डी (नालन्दा) एवं

देसरी (वैशाली) में क्रमशः सब्जी एवं फल के एक-एक सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स की स्थापना की जा रही है। मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक सब्जी की खेती तथा कृषकों के बीच टिशू कल्चर पौधे उपलब्ध कराने संबंधी विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

38. मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के अन्तर्गत प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम, आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम, प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम, समेकित कीट व्याधि प्रबंधन कार्यक्रम, खूंटी प्रबंधन कार्यक्रम, गन्ने के साथ अन्तरवर्ती फसल उत्पादन कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण, कृषक प्रशिक्षण आयोजन कार्यक्रम इत्यादि को शामिल किया गया है।

39. सरकार के प्रयासों और लोगों की भागीदारी के फलस्वरूप राज्य का हरित आवरण, जो वर्ष 2011 में लगभग 9.79 प्रतिशत था, वह बढ़कर वर्तमान में 12.88 प्रतिशत हो गया है। इसे वर्ष 2017 तक 15 प्रतिशत करने हेतु सरकार द्वारा हरियाली मिशन के तहत अनेक योजनायें चलायी जा रही हैं। कृषि वानिकी योजना, निजी पौधशाला योजना एवं वृक्ष संरक्षण आदि योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब तक लगभग 19 करोड़ 50 लाख वृक्षों का रोपण किया गया है।

40. पशु एवं मत्स्य संसाधन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवा, पशुपालकों को एम्बुलेट्री वैन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में कार्यरत सभी पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क प्राणरक्षक पशु दवा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2015-16 तक 500 पशु चिकित्सालयों के नवनिर्मित भवन को हस्तगत कराया जा चुका है। राज्य में पशु विज्ञान, गव्य विज्ञान एवं मत्स्य तकनीक के अध्ययन एवं शोध कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।

41. राज्य में डेयरी इकाई की स्थापना हेतु समग्र गव्य विकास योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थी को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में दुग्ध संग्रहण अभिवृद्धि हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन, दुग्ध संग्रहण केन्द्र एवं स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र तथा स्वचालित मिल्कींग मशीन उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

42. राज्य में मत्स्य विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मत्स्य पालकों द्वारा अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हेतु 93 हजार 296 हेक्टेयर तालाबों, 9 लाख 41 हजार हेक्टेयर आर्द्र जल क्षेत्र, 26 हजार 303 हेक्टेयर जलाशय, 9 हजार हेक्टेयर मन तथा 3 हजार 200 किलोमीटर नदियों का विकास तथा फिश फेडरेशन एवं फिश-फीड-मील उद्योग की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में बिहार मीठा जल गछली उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है।

43. अल्पकालीन सहकारी कृषि ऋण वितरण के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2015-16 में 2 अरब 68 करोड़ रुपये खरीफ ऋण एवं 51 करोड़ 44 लाख रुपये रबी ऋण वितरित किया गया है। वर्तमान वर्ष 2015-16 में किसानों से अधिप्राप्ति किये गये धान का, पैक्स-व्यापार मंडलों द्वारा मिलिंग कराकर सी.एम.आर. (चावल) राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान शत-प्रतिशत आर.टी.जी.एस.-एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से बैंकों के द्वारा किया जा रहा है। 18 फरवरी, 2016 तक 5 लाख 36 हजार मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है।

44. कृषि रोड मैप के अन्तर्गत पैक्स-व्यापार मंडलों द्वारा भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि के लिए नये गोदाम निर्माण कराने के निमित्त अब तक 2 हजार 975 गोदामों का निर्माण कर 12 लाख 63 हजार मेट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है तथा 1 हजार 583 गोदामों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन हेतु बायोमास गैसीफायर आधारित चावल मील स्थापना के लिए कुल 225 चावल मील-सह-गैसीफायर का निर्माण पूरा हो गया है तथा 92 में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

45. राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से 29 लाख 25 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है यथा विष्णु वीयर, जगन्नाथ वीयर, कर्मनासा पम्प नहर, मोर वीयर, दुर्गावती जलाशय योजना, पतित वीयर योजना, सोलहंडा वीयर योजना, लवाईच रामपुर बराज योजना, उदेरास्थान बराज योजना आदि योजनाओं का क्रियान्वयन से 26 हजार 497 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने की संभावना है। राज्य सरकार के सहित सिंचाई योजना के अन्तर्गत कुल 161 अदद योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इससे कुल 67 हजार 386 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा। आर0 आई0 डी0 एफ0 योजनान्तर्गत कुल 27 अदद योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिससे 27 हजार 549 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा। राज्य के अन्दर नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना अन्तर्गत बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा लिंक नहर योजना, बकसोती में बराज बनाकर सकरी-नाटा लिंक योजना एवं कोशी-मेची लिंक योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा गया था। केन्द्रीय जल आयोग के स्तर पर इन योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के कार्यों में प्रगति हुई है। इन्द्रपुरी जलाशय योजना के निर्माण हेतु पूर्ण जलाशय स्तर एवं अधिकतम जल स्तर निर्धारण के चिरलंबित मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से सहमती बनी है।

46. लघु सिंचाई के क्षेत्र में अनुदान आधारित बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, राज्य के सभी प्रखंडों में प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत कुल 19 हजार 812 नलकूप लगाकर 20 हजार एकड़ से अधिक सिंचाई क्षमता के सृजन का कार्यक्रम है।

47. सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना के सर्वेक्षण के आधार पर खाद्य सुरक्षा लागू करने वाले राज्यों में बिहार अग्रणी है। निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्त के आलोक में पहचान किये गये 8 करोड़ 57 लाख पात्र लाभुकों को संशोधित दर पर 4 लाख 57 हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न का मासिक आवंटन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शत-प्रतिशत अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति पात्र परिवारों को इस योजना के तहत आच्छादित करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में खाद्यान्न-किरासन तेल की कालाबाजारी के निरीक्षण के क्रम में कुल 322 छापेमारियों की गयीं और दर्ज प्राथमिकी की संख्या 163 है तथा 138 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

48. मनरेगा अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी 177 रुपये दी जा रही है, जबकि इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा मजदूरी की दर 162 रुपये निर्धारित है। मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2015 तक 3 करोड़ 52 लाख 69 हजार मानव दिवस सृजन किये गये एवं 10 अरब 14 करोड़

